967 छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं आइआइटी दिल्ली में। पहले चरण की प्लेसमेंट प्रक्रिया में इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले 10 फीसद ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 20 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

कुलपति ने दिए वैकल्पिक माध्यम से परीक्षा के निर्देश

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन की तरफ से गुरुवार को परिपत्र जारी करते हुए छात्रों को जानकारी दी है कि वैकल्पिक माध्यम से सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संस्थान में मौजूदा समय में छात्रों द्वारा छात्रावास की फीस वृद्धि को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार इन प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा स्कूलों को बंद किया गया है। इसके कारण इनमें सेमेस्टर परीक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के पीएचडी छात्र एवं वामपंथी छात्र संगठन आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साई बालाजी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई स्कूलों के डीन की तरफ से ईमेल के जरिये सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्नपत्र भेजा जा रहा है। छात्रों से ईमेल के जरिये भेजे गए प्रश्नपत्र के जवाब को वॉट्सएप के जरिये मांगा जा रहा है। यह व्यवस्था गलत है। (जासं)

केजरीवाल व पीके लांच करेंगे आप का पहला चुनावी कैंपेन

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी कैंपेन की कमान संभालने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत शुक्रवार को प्रशांत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई में आप का पहला चुनावी कैंपेन लांच किया जाएगा। इसे 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को काउंटर करने की योजना के रूप में भी देखा जा रहा है। मोदी की रैली से ठीक पहले आप का चुनावी कैंपेन शुरू करके प्रशांत किशोर दिल्ली विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की तैयारी में हैं। इस बार आप नए नारे और नई टैगलाइन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। इसके लिए अधिसूचना जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है। (जासं)

90 कैप्सूल में 880 ग्राम ड्रग निगलकर पहुंचा यात्री पकड़ा

नई दिल्ली : ब्राजील से 90 कैप्सूल में 880 ग्राम ड्रग निगलकर दिल्ली पहुंचे एक यात्री को आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा है। उसके पेट में ड्रग होने की पुष्टि होने पर कोर्ट के आदेश के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाकर उसके पेट से ड्रग वाले 90 कैप्सूल निकाले गए। आरोपित वेनेजुएला का नागरिक है। कस्टम के मुताबिक जांच अधिकारियों ने एक संदिग्ध की पहचान कैप्सूल में ड्रग निकलकर तस्करी करने में माहिर तस्कर के रूप में की। शक के आधार पर उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। (जासं)

वायु प्रदूषण से निपटने में स्मॉग टॉवर प्रभावी नहीं : अमेरिकी विशेषज्ञ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता की भी बताई कमी
- करोड़ों रुपये इस पर खर्च करने के बजाय किसानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने की बताई जरूरत
- कहा, शहरी क्षेत्रों के अलावा कोई भी सतर्क नहीं

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग टॉवर लगाने जैसे विकल्पों को अजमाने की तैयारियां भले ही जोरों पर है, लेकिन हवा की गुणवत्ता पर काम करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ प्रकाश दोराईस्वामी इसे प्रभावी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ना तो यह वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान है और ना ही इससे यह खत्म होने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि इसके पैदा होने वाले स्रोतों को खत्म किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे लगाने पर जो करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे, उसकी जगह किसानों को तकनीकी मदद मुहैया कराने में मदद दी जानी चाहिए, ताकि वह फसलों के अवशेष को न जलाएं। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे लोग निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें।

वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर काम करने वाली अमेरिका की प्रतिष्ठित एजेंसी आरटीआइ इंटरनेशनल के प्रमुख वैज्ञानिक (वायु गुणवत्ता) दोराईस्वामी गुरुवार को दिल्ली में थे।

'जागरण' से विशेष बातचीत में दोराईस्वामी ने बताया कि वायु प्रदूषण को लेकर उन्होंने हाल ही में दिल्ली, चंडीगढ़ सहित देश के कई शहरों में कार्यशालाएं आयोजित की थीं, जिनमें सरकारी एजेंसियों के साथ स्थानीय प्रशासन, तकनीकी संस्थान और प्रदूषण को लेकर काम करने वाली अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान प्रदूषण के जो तीन बड़े कारण सामने आए, उनमें पहला- निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, दूसरा- फसलों के अवशेष को जलाया जाना और तीसरा- वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर में सही मायनों में कमी लाना है तो इन्हीं तीन मुख्य बिंदुओं को लेकर जमीनी स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने इसे लेकर कुछ उपाय भी बताए हैं। साथ ही कहा कि वह इससे जुड़े सभी सुझाव भारत और अमेरिका की सरकारों को भी सौंपेंगे। साथ ही उम्मीद जताई कि इससे जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट जनवरी के अंत तक दे देंगे।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसे लेकर अपने स्तर पर सभी प्रभावी कदम उठा रही है। उनके पास इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम है। लेकिन इसमें सफलता तभी मिलेगी, जब जमीनी स्तर पर काम होगा। फिलहाल अभी इसमें कमी है।

स्मॉग टॉवर को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह ठीक एयर प्यूरीफायर जैसा ही है जो बंद कमरे की हवा को साफ रखने में मदद करता है। लेकिन यह तभी तक ठीक से काम करता है, जब तक घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। यदि दरवाजे और खिड़कियां खुली रहेंगी, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को खत्म किया जाए, ताकि प्रदूषण पैदा ही न हो।

गौरतलब है कि यह एजेंसी मौजूदा समय में भारत में नॉर्थ अमेरिकन सेंटर के साथ मिलकर वायु प्रदूषण से निपटने में सरकार को नीतिगत मदद दे रही है। इससे पहले वर्ष 2016-17 में भी इस एजेंसी ने भारत में वायु प्रदूषण को लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी थी। बाद में उसके कई सुझावों को सरकार ने अपने प्लान में दी जगह दी थी।

बढ़ा प्रदूषण, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर इंडेक्स

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बादल छाए रहने और हवा की गति भी मंद होने के कारण गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर और बढ़कर खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 362 दर्ज किया, जो किबहुत खराब श्रेणी का रहा। मौसमी परिस्थितियों में सुधार न होने पर शुक्रवार को भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम ही है। एनसीआर के कुछ जगहों पर एयर इंडेक्स 400 का आंकड़ा पार कर गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकता है।

दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स	
दिल्ली	362
गाजियाबाद	391
फरीदाबाद	375
ग्रेटर नोएडा	351
नोएडा	378
गुरुग्राम	298

सोमवार से दो जगह शुरू होगा पार्किंग का ट्रायल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : लंबे समय से चली रही कवायद के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोमवार से दो जगहों पर पार्किंग प्लान का ट्रायल शुरू हो जाएगा। यह ट्रायल कमला नगर और कृष्णा नगर मार्केट में दो सप्ताह तक चलाया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की टीम खुद वहां का निरीक्षण करेगी और ट्रायल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी।

यह फैसला इंडिया हेबीटेट सेंटर स्थित ईपीसीए कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में उपस्थित रहे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इस दिशा में निर्देश दे दिए गए हैं। लाजपत नगर में भी यह ट्रायल इसी हफ्ते शुरू कर दिया जाएगा। यदि यह तीनों पायलट प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो फिर इसी मॉडल पर पूरी दिल्ली के लिए पार्किंग प्लान तैयार कर उसे लागू किया जाएगा। ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल के मुताबिक दोनों जगहों पर संबंधित नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को अपनी-अपनी सड़कों पर मिलकर यह काम शुरू करने को कहा गया है।

राजधानी में फ्री वाई-फाई सेवा शुरू

एक और तोहफा ▶ केजरीवाल ने आइटीओ बस स्टॉप से योजना का किया शुभारंभ

अगले छह माह में पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को फ्री वाई-फाई दिल्ली का सपना साकार किया। उन्होंने आइटीओ बस स्टॉप से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत दिल्ली भर में 109 हॉट स्पॉट शुरू किए गए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली दुनिया में पहला ऐसा शहर बन गया, जहां सरकार की तरफ से पूरे शहर के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है। अब प्रति सप्ताह 500 हॉट स्पॉट लगेंगे। उन्होंने हॉट स्पॉट के जरिये ही दिल्ली विश्वविद्यालय में इस योजना का शुभारंभ कर रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात की। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को भी इस योजना के शुरू होने पर बधाई दी।

केजरीवाल ने कहा कि अगले छह माह में पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इससे प्रति 500 मीटर पर लोग फ्री वाई फाई की सुविधा ले सकेंगे। इससे 22 लाख लोग एक साथ इंटरनेट सर्फ कर सकेंगे। एक उपभोक्ता को प्रतिमाह 15 जीबी डाटा मुफ्त मिलेगा। इस योजना पर कुल 99,50,38,560 रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले हॉट स्पॉट की कार्यप्रणाली पर पूरी नजर रखेंगे। देखेंगे कि यह कैसा काम कर रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में शेष दिल्ली में भी हॉट स्पॉट लगा देंगे।

80 मीटर के दायरे में करेंगे काम : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी के चार हजार बस स्टॉप के ऊपर और सात हजार अन्य जगहों पर हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इनमें आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन व अन्य स्थान भी शामिल है। सभी हॉट स्पॉट 80 मीटर के दायरे में काम करेंगे। 6100 हॉट स्पॉट 200 एमबीपीएस के होंगे और 5900 हॉट स्पॉट 50 एमबीपीएस स्पीड के होंगे।

रेंज बदलने पर भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा इंटरनेट : मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हॉट स्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक एप बनाया गया है। इसके जरिये उपभोक्ता को अपनी केवाइसी की डिटेल भरनी होगी। केवाइसी भरने के बाद यूजर के फोन में ओटीपी आएगा। वह ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट का कनेक्शन चालू हो जाएगा। यदि आप एक सप्ताह तक अपने हॉट स्पॉट के जोन से निकलकर दूसरे के जोन में जाते हैं, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा बल्कि वह दूसरे हॉट स्पॉट की रेंज में जाकर ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएगा।

सीसीटीवी को भी हॉट स्पॉट से जोड़ा जाएगा : दिल्ली में लगे सीसीटीवी को फ्री वाई फाई सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली को और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2015 में सरकार में आते ही हॉट स्पॉट पर काम शुरू हो गया था। रेस्टो कंपनी को वाई फाई का अनुबंध दिया गया है। दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरों एवं वाई-फाई का मेंटेनेंस दिल्ली सरकार करेगी।

आइटीओ स्थित बस स्टॉप से फ्री वाई-फाई योजना के शुभारंभ के अवसर पर बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन(बाएं)। जागरण

केंद्र सरकार पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फ्री वाई-फाई योजना की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ही के दिन दिल्ली में अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के निर्देश के बाद टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट, वायस और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी थीं। इसके चलते कई घंटों तक लोगों को फोन और इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने में परेशानी हुई।

इन जगहों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा शुरू

- कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
- कश्मीरी गेट आइएसबीटी
- आइटीओ बस स्टैंड
- मंडी हाउस बस स्टैंड
- दिल्ली सचिवालय
- इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
- दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
- सराय काले खां बस स्टैंड

संपत्तियों के विकास से नहीं बढ़ पा रही मेट्रो की कमाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- यात्रियों के किराये पर ही निर्भर डीएमआरसी
- मेट्रो का घाटा बढ़ा, वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई बात

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को संपत्तियों के विकास (प्रोपर्टी डेवलपमेंट) और आय के अन्य विकल्प तलाशने की बात कह चुका है। लेकिन व्यावसायिक संपत्तियों के विकास में डीएमआरसी को खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इस वजह से संपत्तियों के विकास से मेट्रो की कमाई अधिक नहीं बढ़ पा रही है। यात्रियों के किराये पर भी डीएमआरसी की निर्भरता बनी हुई है। हालांकि परिचालन की कमाई के लिहाज से मेट्रो फायदे में है, लेकिन लोन व हर तरह की देनदारी चुकाने के बाद डीएमआरसी का घाटा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। डीएमआरसी की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में डीएमआरसी को विभिन्न स्रोतों से कुल छह हजार 461 करोड़ 52 लाख राजस्व मिला। कुल खर्च चार हजार 498 करोड़ 77 लाख रहा। इस तरह मेट्रो को एक हजार 962 करोड़ 75 लाख फायदा हुआ, लेकिन वित्तीय समायोजन के बाद डीएमआरसी ने 462.23 करोड़ का घाटा दिखाया है। इसके पिछले वित्त वर्ष में घाटा महज 93.14 करोड़ था। इसका एक कारण तो यह है कि वर्ष 2017 में दोगुना किराया वृद्धि के बाद परिचालन से मेट्रो की कमाई 38.39 फीसद तक बढ़ गई थी। वर्ष 2018-19 में मेट्रो का नेटवर्क 251.68 किलोमीटर से बढ़कर 343.63 किलोमीटर हो गया। इसके बावजूद परिचालन से मेट्रो की कमाई में 18.35 फीसद ही बढ़ोतरी हो पाई। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि फेज तीन के सभी कॉरिडोर पर परिचालन शुरू होने के बाद भी मेट्रो में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीएमआरसी ने इस बार वार्षिक रिपोर्ट में भी मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले यात्रियों की संख्या कम बढ़ने के कारण परिचालन से राजस्व में 555.54 करोड़ की बढ़ोतरी हो पाई। इस तरह डीएमआरसी ने परिचालन से तीन हजार 582 करोड़ 80 लाख कमाई की। जबकि संपत्ति विकास से महज 97.28 करोड़ राजस्व मिला। किराये के बाद डीएमआरसी को सबसे ज्यादा राजस्व दूसरे शहरों की मेट्रो परियोजनाओं में कंसल्टेंसी सेवा के रूप में मिलता है।

उल्लेखनीय है कि कई नए स्टेशनों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित करने की योजना है ताकि मेट्रो का राजस्व बढ़ सके। डीएमआरसी ने जनकपुरी में आवासीय परिसर विकसित करने की योजना भी बनाई थी। इस योजना के तहत डीएमआरसी ने फ्लैट बनाकर विक्री करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा व्यावसायिक संपत्ति विकास की कई योजनाएं हैं, जो परवान नहीं चढ़ पा रही हैं।

'दिल्ली में हिंसा के लिए भाजपा व आप जिम्मेदार'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार एवं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने का घिनौना प्रयास किया है। इससे आज दिल्ली की जनता न केवल आहत है, बल्कि अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रही है।

चोपड़ा गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में ब्लॉक व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की सभा में बोल रहे थे। बैठक को चोपड़ा के अलावा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद, मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा और राजेश लिलौठिया ने भी संबोधित किया। चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, दिल्ली की आम जनता भयभीत है और लोग अपने दफ्तर से न घर पहुंच पा रहे हैं और न ही रोजमर्रा के काम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद होने, जगह जगह ट्रैफिक जाम होने व धारा 144 लगने से अफरातफरी का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के इन हालातों के लिए भाजपा व आप ही पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे दिल्ली में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करें, साथ ही पीड़ित लोगों की मदद भी करें।

कीर्ति आजाद ने कहा कि सरकार में बैठे लोग ही जब हिंसा कराएंगे व कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो देश और दिल्ली का शासन कैसे चलेगा, यह समझ से परे है। उन्होंने दिल्ली में घटी घटनाओं गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा करते हुए सभी गिरफ्तार आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग भी की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा द्वारा रखे गए एक प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रस्ताव में राजधानी में जनजीवन को अस्तव्यस्त करने और दिल्ली को हिंसा के हवाले करने के लिए जिम्मेदार भाजपा व आप की निंदा की गई।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जिला कमेटी और ब्लाक अध्यक्षों के साथ हुई बैठक को संबोधित करते प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा। सौजन्य : कांग्रेस

125 डिपार्टमेंटल स्टोरों पर आज से नहीं मिलेगी शराब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के 125 डिपार्टमेंटल स्टोरों पर शुक्रवार से शराब की ब्रिकी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने के आरोप में आबकारी विभाग ने इन स्टोरों का एल-12 और एल-12 एफ लाइसेंस निरस्त कर दिया, जो शराब की बिक्री के लिए आवश्यक होता है। विभाग की छापेमारी के बाद दिल्ली सरकार ने यहां शराब की बिक्री बंद करने का बड़ा फैसला किया है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दो-तीन महीने पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ दिल्लीभर में 125 डिपार्टमेंटल स्टोरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान यहां तय मात्रा से ज्यादा शराब मिली थी जबकि एल-12 और एल-12 एफ लाइसेंस के अनुसार डिपार्टमेंटल स्टोर के कुल उत्पादों में शराब की मात्रा 12 फीसद से अधिक नहीं हो चाहिए। छापेमारी के दौरान इन डिपार्टमेंटल स्टोरों पर 50 से लेकर 90 फीसद मात्रा में शराब मिली थी। इसके चलते 40 स्टोरों को उसी समय सील कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद विभाग ने इनकी सील खोल दी थी। शुक्रवार से शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर गई है।

निर्भया के दोषी पवन की याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- हाई कोर्ट ने वकील पर 25 हजार का जुर्माना लगाया
- दोषी पवन ने अपराध के समय खुद को बताया था नाबालिग

वर्ष 2012 में वारदात के समय नाबालिग होने का दावा करते हुए निर्भया मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने पवन के अधिवक्ता एपी सिंह के बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया। पीठ ने कहा कि उक्त धनराशि निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था निर्मल छाया के पक्ष में एक सप्ताह के अंदर भुगतान की जाए। पीठ ने पवन की आयु से जुड़ा फर्जी शपथपत्र दाखिल करने पर दिल्ली बार काउंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इस मामले में पवन के अलावा विनय, मुकेश और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि पवन कुमार ने नाबालिग होने का दावा इससे पहले पुनर्विचार याचिका में भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुवार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर एपी सिंह पीठ के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दूसरे पक्ष के संबंध में जानकारी दिए बगैर ही अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की बात करते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। इस पर पीठ ने सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित भी कर दी। कुछ ही देर बाद पीड़िता की मां की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय लाऊ, अधिवक्ता जितेंद्र झा एवं अधिवक्ता सीमा सिद्धार्थ ने पीठ को जानकारी दी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जा चुका है और इस याचिका का कोई आधार नहीं है।

याचिका सिर्फ दोषियों की फांसी की सजा को टालने के उद्देश्य से लगाई गई है। पीड़िता के परिजन भी अदालत में मौजूद थे। इसके बाद पीठ ने अधिवक्ता एपी सिंह को अपने कर्मचारियों के माध्यम से फोन, एसएमएस और ईमेल के जरिये दोपहर बाद सुनवाई होने के संबंध में जानकारी भेजी। लेकिन एपी सिंह ने अदालत में आने की जहमत नहीं उठाई। ढाई बजे जब अदालत दोबारा बैठी और सुनवाई शुरू हुई तो पीठ ने इसे अपने फैसले में दर्ज किया।

पीड़िता की मां ने किया स्वागत : निर्भया की मां ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अदालत ने अपना काम किया और मैं इस फैसले से संतुष्ट हूं। दोषी और उसके अधिवक्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया। जुर्माना लगाकर अदालत ने मामलों को लटकाने वालों को सख्त संदेश दिया है।

आयु के संबंध में दी गलत जानकारी

पवन कुमार ने याचिका में दावा किया कि स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार उसका जन्म 8 अक्टूबर 1996 को हुआ था और घटना के दौरान वह नाबालिग था। ऐसे में उसे नाबालिग होने का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि पुलिस की जांच और सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता ने बताया था कि पवन का जन्म 17 जुलाई, 1992 को हुआ था। इससे 16 दिसंबर, 2012 को हुई वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म की घटना के दौरान वह 18 साल का था।

यह कहा याचिका में

याचिका में दोषी पवन कुमार ने आरोप लगाया कि उम्र की जांच के लिए अधिकारियों ने उसकी हड्डी का परीक्षण नहीं किया था। घटना के समय नाबालिग होने के कारण वह जेजे एक्ट की धारा 7ए के तहत किसी भी अदालत के समक्ष जा सकता है। अंतिम फैसला होने के बावजूद किसी भी स्तर पर इसकी पहचान कराई जा सकती है।

योजना

हर फायर स्टेशन को अलग से स्टॉफ देकर जांच के लिए अलग विंग बनाने का है प्रस्ताव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में आग से सुरक्षा व्यवस्था हो सकेगी मजबूत

आग बुझाने व जांचने की टीमें होंगी अलग-अलग

रजनीकान्त मिश्र, नोएडा

दिल्ली के अनाज मंडी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में 43 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश फायर सर्विस आग से सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रहा है। पुरानी औद्योगिक इकाइयों की जांच से लेकर नई बिल्डिंग की जांच के लिए फायर स्टेशन में अलग से विंग बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अग्निशमन विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया गया है। फायर स्टेशनों में बनने वाली विंग पुरानी बिल्डिंग की जांच के अलावा अन्य बिल्डिंग की एनओसी जारी करने से पहले निरीक्षण करेगी। उसके बाद ही उन बिल्डिंग की एनओसी जारी होगी। इस प्रकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की तरफ से मेरठ परिक्षेत्र के उप निदेशक अमन शर्मा की टीम ने तैयार किया है।

यह प्रस्ताव अग्निशमन मुख्यालय लखनऊ भेजा जाएगा। प्रयास है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कराया जाए। मुख्यालय से अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो खास कर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर व लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।

आग बुझाने के साथ जांच में आ रही है मुश्किलें : खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 15 हजार औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। फायर स्टेशनों में पहले से ही फायर मैन सहित अन्य स्टॉफ की भारी कमी है और काम का दबाव भी रहता है। ऐसे में फायर फाइटिंग के साथ इन सभी औद्योगिक इकाइयों की प्रति वर्ष जांच करना अग्निशमन विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। अग्निशमन विभाग की तरफ से तैयार हो रहे प्रस्ताव पर मंजूरी मिलती है और इस अलग विंग का गठन होता है तो सबसे अधिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ गाजियाबाद को फायदा मिलेगा। इन शहरों में औद्योगिक इकाइयों के साथ बहुमंजिला इमारत, कामर्शियल बिल्डिंग व बाजारों की आग से सुरक्षा व्यवस्था की आसानी से निगरानी हो सकेगी।

आग बुझाने के साथ सभी बिल्डिंग की जांच करना फायर स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हर फायर स्टेशन पर एक अलग विंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे मुख्यालय को भेजा जाएगा। इसके लिए अलग से फोर्स की भी मांग की जा रही है।

-अमन शर्मा, उप निदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र

जामिया हमदर्द को मिले नए कुलाधिपति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जामिया हमदर्द संस्थान (डिम्ड विश्वविद्यालय) में सैयद शाहिद मेहदी को नया कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। उन्होंने निवर्तमान कुलाधिपति डॉ हाबेल खुराकीवाला का स्थान ग्रहण किया है। वह संस्थान के चौथे कुलाधिपति बने हैं।

मेहदी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के एल्युमिनी हैं। उन्होंने एएमयू से हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस में एमए की। इसके बाद वर्ष 1963 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में देश भर में इस बैच में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बतौर आइएएस, उन्होंने केंद्र सरकार व राज्य सरकार में भी कई पद संभालें। इससे पहले वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति का पद भी वर्ष 2000 से 2004 के दौरान संभाल चुके हैं। इटली की राजधानी रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन में भारत सरकार की ओर से वैकल्पिक स्थायी प्रतिनिधि के पद पर भी रह चुके हैं।

'विजय गोयल ने दिल्ली की जनता का अपमान किया'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- संजय सिंह बोले, अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें भाजपा सांसद

भाजपा सांसद विजय गोयल द्वारा दिल्ली की जनता पर की गई टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। आप का कहना है कि विजय गोयल द्वारा यह कहना कि दिल्ली की जनता मुफ्त की चीजों के बदले में अपना वोट बेचती है, सीधे तौर पर दिल्लीवासियां का अपमान करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने गोयल से दिल्ली के निवासियों से माफी मांगने की भी मांग की है। उनका कहना है कि गोयल के बयान से साफ हो जाता है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आने पर जनता को मिल रही सभी मुफ्त सुविधाओं को खत्म कर दिया जाएगा।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार का यह फर्ज होता है कि वह अपने राज्य की जनता को मूलभूत जरूरतों की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए और अगर केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा अपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो इसके लिए केजरीवाल को लक्ष्य करना ठीक बात नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं,